

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1432
मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

भिवंडी की बुनकर सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण

1432. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भिवंडी की बुनकर सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है, यदि हाँ, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार भिवंडी की सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण के लिए कोई पायलट योजना प्रस्तावित है या शुरू करने का विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भिवंडी की सहकारी समितियाँ जीएसटी के बोझ तले दबी हुई हैं, यदि हाँ, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बना रही है;
- (ङ) क्या भिवंडी की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)**

(क) से (घ) जिन सहकारी समितियों का उद्देश्य केवल एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I-संघ सूची की प्रविष्टि 44 और केंद्रीय प्रशासित बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं। एक राज्य तक सीमित उद्देश्यों वाली सहकारी समितियां संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II-राज्य सूची की प्रविष्टि 32 और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होती हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा रुण बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 63क के अनुसार विकास प्रयोजनों के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि (CRRDF) की स्थापना की गई है।

भारत सरकार ने शुरू में 63,000 पैक्स को 2516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित किया है, जिसे अब बढ़ाकर 2925.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 73,492 पैक्स को कवर किया गया है, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना शामिल है। राज्य-वार ब्योरा संलग्नक के में दिया गया है। महाराष्ट्र में, इस परियोजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत पैक्स 12000 है। जिला-वार ब्योरा संलग्नक (ख) में दिया गया है। भिवंडी, डिजिटलीकरण पहल के हिस्से के रूप में ठाणे जिले के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वस्तु नीति 2023-28 के अंतर्गत, यदि प्लेन-पावरलूम मालिक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-आधारित मशीनरी में अपग्रेड करने का विकल्प चुनते हैं, तो राज्य सरकार भिवंडी क्षेत्र में पावरलूम उद्योग के आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए महाप्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Maha-TUFS) के माध्यम से पावरलूम सहकारी समितियों और निजी पावरलूम इकाइयों दोनों को पूँजीगत सब्सिडी प्रदान करेगी। महाराष्ट्र सरकार पावरलूम सहकारी समितियों को शेयर पूँजी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, पावरलूम सहकारी समितियों और निजी पावरलूम इकाइयों दोनों को बिजली सब्सिडी और पूर्व/पुरानी वस्तु नीति के तहत पूँजी और ब्याज सब्सिडी भी संवितरित की जा रही है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए ई-टेक्सटाइल पोर्टल लॉन्च किया है कि महाराष्ट्र में कपड़ा उद्योग के लिए सभी लाभ आसानी से सुलभ हों।

(ङ) भिवंडी, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा सहायता प्राप्त वस्तु सहकारी समितियों का ब्योरा संलग्नक-ग में दिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति (30 जून 2025)

क्रम सं	राज्य	स्वीकृत पैक्स	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए
1.	महाराष्ट्र	12,000	11,954
2.	राजस्थान	7,468	5,900
3.	गुजरात	5,754	5,627
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	3,048
5.	कर्नाटक	5,682	3,765
6.	मध्य प्रदेश	5,188	4,428
7.	तमिलनाडु	4,532	4,531
8.	बिहार	4,495	4,460
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	3,145
10.	पंजाब	3,482	3,408
11.	ओडिशा	2,711	-
12.	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021
13.	छत्तीसगढ़	2,028	2,028
14.	हिमाचल प्रदेश	1,789	965
15.	झारखण्ड	2,797	1,414
16.	हरियाणा	710	609
17.	उत्तराखण्ड	670	670
18.	असम	583	579
19.	जम्मू और कश्मीर	537	536

20.	त्रिपुरा	268	207
21.	मणिपुर	232	175
22.	नागालैंड	231	64
23.	मेघालय	112	99
24.	सिक्किम	107	103
25.	गोवा	58	45
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	46
27.	पुड़ुचेरी	45	43
28.	मिजोरम	49	25
29.	अरुणाचल प्रदेश	14	11
30.	लद्दाख	10	10
31.	दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	4
	कुल	73,492	59,920

संलग्नक- ख

पैक्स कम्प्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति-महाराष्ट्र (30 जून 2025 तक)

क्रम सं	जिले का नाम	अनुमोदित पैक्स	ईआरपी पर ऑनबोर्ड किए गए
1	अहमदनगर	946	946
2	धुले	175	175
3	जलगांव	352	352
4	जालना	200	191
5	कोल्हापुर	1751	1725
6	नंदुरबार	111	111
7	पालघर	93	93
8	पुणे	1192	1192
9	रायगढ़	122	122
10	रत्नागिरी	287	282
11	सांगली	650	639
12	सातारा	933	942
13	सिंधुदुर्ग	214	214
14	ठाणे	144	144
16	अकोला	412	411
17	अमरावती	214	219
18	औरंगाबाद	305	305
19	बुलढाणा	201	200
20	हिंगोली	156	155
21	नागपुर	162	162
22	नासिक	614	615
23	परभणी	149	149
24	वाशिम	424	424
25	यवतमाल	210	210
27	बीड	200	200
28	भंडारा	135	135
29	चंद्रपुर	179	179
30	गढ़चिरोली	101	101
31	गोदिया	121	121

32	लातूर	482	475
33	नांदेड़	64	64
34	उस्मानाबाद	156	156
35	सोलापुर	545	545
कुल योग		12,000	11,954

महाराष्ट्र के भिवंडी में एनसीडीसी द्वारा सहायता प्राप्त वस्त्र सहकारी समितियों का ब्योरा

क्रम सं.	सहकारी समिति का नाम	संस्थीकृति वर्ष	उद्देश्य	जारी की गई सहायता (लाख रुपये में)
1	मुबस्सारा पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	1996-97	मार्जिन राशि	24.98
2	अजंता पावरलूम कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	1996-97	मार्जिन राशि	9.00
3	स्वामी समर्थ यन्त्रमार्ग औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित	2000-01	अवसरंचना	11.80
कुल				45.78

नोट: उपर्युक्त सहकारी समितियों को महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से एनसीडीसी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें राज्य सरकार एनसीडीसी सहायता का प्राथमिक उधारकर्ता थी।

इसके अलावा एनसीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में PMMSY योजना के तहत एक FFPO उसगांव मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुक्काम, डाक गणेशपुरी, तालुका भिवंडी, जिला ठाणे, महाराष्ट्र को 4.66 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया है।